भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2737
दिनांक 16 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय गोकुल मिशन और कामधेनु योजना

2737. श्री सागर ईश्वर खंड्रेः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) और कामधेनु योजना के अंतर्गत कर्नाटक, विशेषकर बीदर जिले में वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों के सम्बन्ध में की गई प्रगति का विवरण क्या है;

(ख) नस्ल सुधार, ए.आई. कवरेज और गोकुल ग्राम स्थापना का विवरण क्या है;

(ग) बीदर जिले जैसे सूखा प्रभावित और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ पशुधन ग्रामीण आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, पशुधन उत्पादकता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण क्या है;

(घ) क्या सरकार का बीदर जिले में पशुधन आधारित आजीविका कार्यक्रमों जैसे डेयरी क्लस्टर, चारा विकास, महिला नेतृत्व वाले डेयरी स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) एवं मूल्य संवर्धन इकाइयों को आरंभ करने या विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है और यदि नहीं, तो बीदर जिले को प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं जबकि यह पशुधन पर अत्यधिक निर्भर है एवं ग्रामीण संकट निरंतर बना हुआ है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ) बीदर जिले सहित कर्नाटक में राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के अंतर्गत एआई कवरेज**,** नस्ल विकास और गोकुल ग्रामों की स्थापना के संदर्भ में की गई वास्तविक और वित्तीय प्रगति का विवरण अनुबंध-I में है।

पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के संबंध में राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों को संपूरित करने हेतु भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) पूरे देश में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है**,** जिनमें बीदर जिले जैसे सूखे की आशंका वाले और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां पशुधन ग्रामीण आय का प्रमुख स्रोत है:

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)**:** आरजीएम को देसी नस्लों के विकास और संरक्षण**,** बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाइनों के दूध उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया गया है। इस योजना के तहत किए गए मुख्य प्रयास निम्नलिखित हैं:

(i) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान (AI) कवरेज को बढ़ाना और देशी नस्लों सहित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के सीमन से किसानों के द्वार तक गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करना है। कार्यक्रम की प्रगति को भारत पशुधन/ NDLM (राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन) पर वास्तविक समय में अपलोड किया जाता है**,** जिससे कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले किसानों की ट्रैकिंग की जा सकती है। अब तक 9.36 करोड़ पशुओं को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है, 14.56 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए

गए हैं और 5.62 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है। उत्पादकता में वृद्धि से भाग लेने वाले किसानों की आय में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।

(ii) सेक्स सॉर्टेड सीमन: 90% सटीकता के साथ बछड़ियों का जन्म सुनिश्चित करने के लिए देश में सेक्स-सॉर्टेड सीमन तकनीक प्रारंभ की गई है। यह तकनीक गेम चेंजर है, क्योंकि इससे न केवल दूध उत्पादन बढ़ता है, बल्कि बेसहारा पशुओं की संख्या में कमी लाने में भी मदद मिलती है। भारत में पहली बार, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्थापित सुविधाओं ने देशी गोपशु नस्लों के सेक्स-सॉर्टेड सीमन का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है। ये सुविधाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पांच सरकारी सीमन केंद्रों में स्थित हैं। इसके अलावा, तीन निजी सीमन केंद्र भी सेक्स-सॉर्टेड सीमन की खुराक के उत्पादन में लगे हुए हैं। अब तक निजी सीमन केंद्रों से उत्पादित सीमन की खुराक सहित देश में 128 लाख सेक्स-सॉर्टेड सीमन की खुराक का उत्पादन किया जा चुका है। देशी रूप से विकसित सेक्स-सॉर्टेड सीमन उत्पादन तकनीकी का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 5.10.2024 को किया गया था। इस तकनीकी के कारण सेक्स-सॉर्टेड सीमन की लागत 800 रुपये से घटकर 250 रुपये प्रति खुराक हो गई है। अब तक देश में देशी तकनीकी का उपयोग करते हुए 40 लाख खुराक तक सेक्स-सॉर्टेड सीमन उत्पादन सुविधा स्थापित की जा चुकी है।

सेक्स-सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस कार्यक्रम के अंतर्गत देशी नस्लों के सेक्स-सॉर्टेड सीमन को बढ़ावा दिया जाता है। इस घटक के तहत, सुनिश्चित गर्भधारण की स्थिति में किसानों को सेक्स-सॉर्टेड सीमन की लागत के 50% तक प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(iii) ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAITRI): मैत्री (MAITRI) को किसानों के द्वार पर ही गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। अब तक, 39810 मैत्री (MAITRI) को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जा चुका है।

(iv) इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक का कार्यान्वयन: देश में पहली बार देशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए बोवाइन आईवीएफ तकनीकी को बढ़ावा दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए विभाग ने पूरे भारत में 24 आईवीएफ प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। आईवीएफ तकनीकी का लाभ उठाते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य उन्नत प्रजनन विधियों को किसानों तक पहुँचाना है। प्रत्येक सुनिश्चित गर्भधारण पर 5,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशी नस्लों के विकास को बढ़ावा देना है। कर्नाटक राज्य में केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान (CFSP&TI), हैसरगट्टा, बेंगलुरु में एक आईवीएफ प्रयोगशाला चालू हो गई है।

(v) संतति परीक्षण और वंशावली चयन कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशी नस्लों के सांडों सहित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का उत्पादन करना है। गोपशुओं की गिर और साहीवाल नस्लों तथा भैंसों की मुर्रा और मेहसाना नस्लों के लिए संतति परीक्षण किया जाता है। वंशावली चयन कार्यक्रम के अंतर्गत गोपशु की राठी, थारपारकर, हरियाना और कांकरेज नस्लें तथा भैंस की जाफराबादी, नीली रावी, पंढरपुरी और बन्नी नस्लें शामिल हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादित रोगमुक्त और उच्च आनुवंशिक गुणता वाले देशी नस्लों के सांडों को देश भर के वीर्य परीक्षण केंद्रों को उपलब्ध कराया जाता है। अब तक 4288 उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का उत्पादन किया जा चुका है और उन्हें कर्नाटक में स्थित सीमन केंद्रों सहित सभी सीमन केंद्रों को सीमन उत्पादन के लिए उपलब्ध कराया गया है।

(vi) देशी नस्लों के सीमन सहित, सीमन उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के लिए सीमन केंद्रों को सुदृढ़ करना। अब तक कर्नाटक राज्य के 6 सीमन केंद्रों सहित 47 सीमन केंद्रों को सुदृढ़ करने की संस्वीकृति दी जा चुकी है।

(vii) किसानों में जागरूकता पैदा करना: इस योजना के तहत, किसानों को देशी बोवाइन नस्लों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए प्रजनन शिविर, दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिताएं, बछड़ा-बछड़ी रैलियां, सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

2. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD): एनपीडीडी को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया जाता है:

(i) एनपीडीडी का घटक ''क'' राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/ जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/ स्वयं सहायता समूहों (SHG)/ दुग्ध उत्पादक कंपनियों/ किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरण और प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

(ii) एनपीडीडी योजना का घटक ''ख'' "सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य किसानों की संगठित बाजार तक पहुंच बढ़ाकर, दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके तथा उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता बढ़ाकर दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है।

एनपीडीडी योजना के तहत कर्नाटक में 22 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है, जिनकी कुल लागत 45521.03 लाख रुपये है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 30783.03 लाख रुपये है और इसमें से 23660.11 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर्नाटक सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

बीदर जिले में कार्यान्वयन के लिए संस्वीकृत प्रमुख डेयरी परियोजनाओं का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

3. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO): प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से उबरने के लिए सुलभ कार्यशील पूंजीगत ऋण के संबंध में ब्याज सबवेंशन (नियमित 2% और शीघ्र भुगतान पर अतिरिक्त 2%) प्रदान करके राज्य डेयरी सहकारी संघों की सहायता करना।

4. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF): एएचआईडीएफ पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है, जिससे असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक अधिक पहुंच प्राप्त होती है।

5. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM): व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, धारा 8 की कंपनियों को उद्यमिता विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके और राज्य सरकार को नस्ल सुधार अवसंरचना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सुअर पालन और चरागाह में उद्यमिता विकास तथा नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान केंद्रित करना।
राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अंतर्गत, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) एक महत्वपूर्ण घटक है जिसके तहत ग्रामीण पोल्ट्री प्रजनन फार्मों के साथ-साथ भेड़, बकरी, सूअर, ऊंट, घोड़े और गधे के प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसकी विभिन्न घटकों के लिए अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक है। इसके अतिरिक्त, यह घास (हे), साइलेज, कुल मिश्रित राशन (TMR), चारा ब्लॉक और चारा बीजों के प्रसंस्करण, वर्गीकरण और भंडारण की इकाइयों सहित चारा मूल्यवर्धन इकाइयों को भी सहायता प्रदान करता है। यह सब्सिडी व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs), संयुक्त देयता समूहों (JLGs), किसान सहकारी संगठनों (FCOs)

और धारा 8 कंपनियों के लिए उपलब्ध है। बीदर जिले और पूरे कर्नाटक राज्य में एनएलएम-ईडीपी के तहत अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव अनुबंध-III में दिया गया है।

राज्य सरकार अपनी पशुधन आबादी की आहार और चारे संबंधी मांग को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। केंद्र सरकार देश में चारे के विकास के लिए विभिन्न पहलें कर रही है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करने लिए केंद्र सरकार 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसमें आहार और चारा विकास संबंधी एक उप-मिशन भी शामिल है। यह योजना वर्ष 2014-15 से पूरे देश में कार्य कर रही है। इस मिशन को जुलाई 2021 में पुनर्संरेखित किया गया और मार्च 2024 में संशोधित किया गया। चारा विकास संबंधी उप-मिशन के निम्नलिखित घटक हैं:

(i) गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता
(ii) पशु आहार और चारे से संबंधित उद्यमशीलता कार्यकलाप
(iii) चारा बीज प्रसंस्करण अवसंरचना (प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाई/चारा बीज भंडारण गोदाम) के लिए उद्यमी तैयार करना।
(iv) गैर-वन बंजर भूमि/रेंजभूमि/गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन और वन भूमि से चारा उत्पादन

इसके अलावा, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चारा उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने और राज्य तथा केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य स्तरीय चारा टास्कफोर्स गठित करने का अनुरोध किया है। इन प्रयासों से संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चारे की उपलब्धता बढ़ेगी।

साथ ही, आईसीएआर-भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी ने कर्नाटक के लिए चारा संसाधन विकास योजना तैयार की है, जिसे कार्यान्वयन हेतु राज्यों को भेज दिया गया है।

6. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP): यह योजना पशु रोगों के लिए रोग निरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता के निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के संबंध में है। साथ ही, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएम-केएसके) और सहकारी समितियों के माध्यम से देश भर में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत पशु औषधि का एक नया घटक जोड़ा गया है। इससे सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक औषधियों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनेगा। LHDCP के तहत वर्ष 2025-26 के दौरान कर्नाटक राज्य को कुल 5126.65 लाख रुपये जारी किए गए हैं। बीदर जिले सहित कर्नाटक में कुल 275 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां (MVU) कार्यरत हैं और कुल 1,11,106 किसानों को लाभ हुआ है तथा कर्नाटक में 1,96,620 पशुओं का उपचार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कर्नाटक राज्य में 1.78 करोड़ पशुओं को खुरपका और मुंहपका रोग (FMD) के लिए टीका लगाया गया और 34.73 लाख किसानों को इसका लाभ मिला, जिसमें बीदर जिले में 3.54 लाख पशुओं का टीकाकरण और 75,986 किसानों को लाभ प्राप्त हुआ।

अनुबंध- I

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के विभिन्न घटकों के तहत हुई प्रगति

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2020-25 के दौरान प्रगति			
		कर्नाटक राज्य		बीदर जिला	
		वास्तविक	वित्तीय (लाख रुपये में)	वास्तविक	वित्तीय (लाख रुपये में)
1	राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम	1.71 करोड़ एआई किए गए	4894.78	2.10 लाख एआई किए गए	86.59
2	सेक्स सॉर्टेड सीमन का प्रयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम (ABIP-SS)	53665 एआई किए गए	516.37	188 एआई किए गए	2.29 (एआई तकनीशियनों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन सहित)
3	ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAITRIs)	1450	1523.45	129	41.94
4	गोपशु की अमृत महल नस्ल के विकास और संरक्षण के लिए लिंगदहल्ली , चिक्कमगलुरु, कर्नाटक में गोकुल ग्राम की स्थापना	1	250	-	-
5.	वीर्य केंद्र का सुदृढ़ीकरण	5	3211.82	-	-

अनुबंध- II

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत बीदर जिले के लिए अनुमोदित प्रमुख डेयरी परियोजनाओं का विवरण

परियोजना सं.	**कार्यकलाप**	**कुल राशि (लाख रुपए में)**
NPDD_KA_01B	76 डेयरी सहकारी समितियों के लिए पूंजी निवेश	177.84
NPDD_KA_04F (QMP)	संयंत्र स्तर पर FTIR तकनीकी आधारित दूध एनालाइज़र लगाना	85.00
NPDD_KA_21L (DCS)	36 नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन	66.96
NPDD_KA_22L	दूध शीतलन और दूध परीक्षण प्रयोगशाला सुविधाओं को सुदृढ़ करना	57.00

अनुबंध- III

कर्नाटक में NLM-EDP के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रुपए में)	जारी की गई पहली किस्त की संख्या	जारी की गई पहली किस्त की राशि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई दूसरी किस्त की संख्या	जारी की गई दूसरी किस्त की राशि (करोड़ रुपए में)
कर्नाटक						
1133	801.012	379.12	494	92.6	200	35.26
बीदर जिला						
52	49.7	21.32	33	7.08	10	1.56

*****